

संक्षिप्त समाचार

छात्रों के आंदोलन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, सभी पक्षों को गंभीरता से ले रही सरकार

रांची, एजेंसी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ-साथ छत्र आंदोलन का मुद्दा उठया गया।

झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान जारी करते हुए कहा कि राज्यापाल को वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, मामले की जांच जारी है कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जांच एजेंसियां लगातार मुद्दे पर कार्रवाई कर रही हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है इसपर जल्द ही ठोस निर्णय लेने की दिशा में काम किया जा रहा है।

वहीं, आंदोलन के मुद्दे पर छात्रों से सरकार के किसी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के सवाल पर सीएम ने स्पष्ट रुप जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं छात्रों की मांगें प्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंच रही हैं सीएम ने कहा कि छात्रों सहित सभी पक्षों की बातों को सरकार गंभीरता से ले रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंदोलनरत छात्र अपने मुद्दों को लेकर सीधे सरकार से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में भी सामने आई हैं। गृह मंत्री से इस मुद्दे पर अभी किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस पर विचार किया जाएगा।

बाबूलाल मरांडी ने सर्वदलीय बैठक में उठाया छात्रों का मुद्दा, आंदोलित छात्रों के समर्थन में दिखे जयराम

रांची, एजेंसी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू हो जाएगा। जो 12 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस मानसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। जिसमें 7 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूर्क बजट सदन में पेश किया जाएगा। सत्र के शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जिसमें विधानसभा मानसून सत्र को सुचारु रुप से चलाने को लेकर विचार-विमर्श और चर्चा हुई।

सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छत्र आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को या सरकार के डेलिगेशन को जल्द से जल्द आंदोलित छात्रों से मुलाकात करना चाहिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि इस मुद्दे पर कार्य मंत्रणा समिति बातचीत होगी।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए छ्त्राकृ विधायक जयराम महतो ने कहा मुख्यमंत्री छत्र आंदोलन के मुद्दे पर टाल मटोल कर रहे हैं। बैठक में मैंने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांग रखी है कि जल्द से जल्द छात्रों का आंदोलन खत्म कराया जाए। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के अध्यक्षता में डेलिगेशन छात्रों से मुलाकात करें। जयराम महतो ने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो मैं खुद अनशन पर बैठूंगा।

जिला कृषि पदाधिकारी ने लिया पदभार



दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद की नई जिला कृषि पदाधिकारी अंजना कुमारी ने जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में कृषि कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर निवर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा ने पुष्पफुल भेंट कर उनका स्वागत किया।इससे पहले नई जिला कृषि पदाधिकारी अंजना कुमारी गिरिडीह में असिस्टेंट सॉलल केमिस्ट के पद पर कार्यरत थीं। वहीं निवर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा का पाकुर जिले में स्थानांतरण किया गया है।

बेलगड़िया के छात्रों को मिला आइआइटी (आइएसएम) में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का स्वर्णिम अवसर

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद।धनबाद जिला प्रशासन तथा बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन की संयुक्त पहल के तहत बेलगड़िया के युवाओं को उनत डिजिटल एवं व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ‘डी-युवा’ (धनबाद युथ अपग्रेडेशन थ्रू वोकेशनल एंड एडवांस्ड डिजीटल स्किल्स) कार्यक्रम का शुभारंभ आइआइटी (आइएसएम) में किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, आइआइटी (आइएसएम) के प्रोफेसर धीरज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर दिनेश प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बेलगड़िया के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस योजना को धरातल पर उतारने के जिला प्रशासन विगत एक साल से प्रयासरत था। आइआइटी (आइएसएम) जैसे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना बेलगड़िया के युवाओं के लिए गौरवशाली क्षण है। सभी युवाओं को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए।उपायुक्त ने कहा कि भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र से बेलगड़िया शिफ्ट हुए

बेलगड़िया से आइआइटी (आइएसएम) तक शुरू होगी विशेष बस सेवा



युवा को अच्छी व्यवस्था देने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। यह उसकी एक शुरुआत मात्र है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उपायुक्त ने कहा कि प्रतिवर्ष 900 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 3 वर्ष के लिए रहेगा। जिसे कंप्यूटर में जितना आता है वहीं से कोर्स की शुरुआत होगी। बेलगड़िया के युवाओं के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जिले के युवाओं, विशेष रूप से बेलगड़िया के युवाओं, को आधुनिक तकनीक, कोडिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंट्री और ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर

एप्लीकेशन, डेटा साइंस, पायथन-आधारित डेटा क्यूएरेशन और एनोटेशन व वेब डेवलपमेंट शामिल है। डिजिटल कौशल में सक्षम बनाकर उन्हें भविष्य के रोजगार एवं अवसरों के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको आधुनिक कंप्यूटर लैब और विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनमें कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा।उपायुक्त में सभी छात्रों से प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित नहीं रहने, नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने और कोर्स को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत नेशनल

स्कौल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मानकों के अनुसार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम बैंक ऑफ इंडिया, सोशल फाउंडेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिसॉर्प्सिबिलिटी के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन ए.सी.आइ.सी. आइआइटी (आइएसएम) फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक है। सभी युवा इसका पूरा फायदा उठाएँ। उन्होंने कहा यहां प्रशिक्षण लेने वाले युवा खुशकिस्मत हैं कि उनको देश के सबसे अच्छे सेंटर में ट्रेनिंग मिल रही है। यहां से मिला प्रशिक्षण हमेशा उनकी मदद करेगा।उन्होंने कहा कि युवा जितना सशक्त होगा देश भी उतना सशक्त बनेगा। उन्होंने बेलगड़िया के युवाओं को इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर पूरी लगन और मेहनत से कोर्स पूरा करने का आह्वान किया।कार्यक्रम को बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर दिनेश प्रसाद व आइआइटी आइएसएम के प्रोफेसर धीरज कुमार ने भी संबोधित किया। दोनों ने डिजिटल साक्षरता, भविष्य की चुनौतियां, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा इत्यादि पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम के समापन पर सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार एवं ए.सी.आइ.सी. आइआइटी (आइएसएम) फाउंडेशन की सीईओ डॉ आकांक्षा सिन्हा ने

एमओयू पर हस्ताक्षर किए।इसके बाद उपायुक्त ने आधुनिक कंप्यूटर लैब का भ्रमण किया। उन्होंने छात्रों से संवाद किया और घोषणा की कि हर बैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा को कंप्यूटर या टैबलेट दिया जाएगा। साथ में कहा कि यदि प्रशिक्षण ले रहे 10-12 युवा आसपास के स्कूल-कॉलेज में प्रशिक्षण जारी करना चाहेंगे तो उनके लिए छुट्टी के बाद भी क्लास करने की व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा।बेलगड़िया के युवाओं ने भी उपायुक्त को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। युवाओं ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आइआइटी (आइएसएम) जैसे देश के श्रेष्ठ संस्थान में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। युवाओं ने बेलगड़िया से आइआइटी (आइएसएम) तक के लिए बस सेवा शुरू करने की पहल के लिए भी जिला पशासन को धन्यवाद दिया। वहीं युवाओं के अभिभावकों ने भी जिला प्रशासन को इस पहल की प्रशंसा की। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जोनल मैनेजर अवरतनु चंदा, एलडीएम अमित कुमार, बीओआइ कंबाइंड बिल्डिंग ब्रांच के मैनेजर अभिजीत गुप्ता, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस के पदाधिकारी, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में बेलगड़िया से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए युवा तथा उनके अभिभावक उपस्थित थे।

दुमका में आकाशीय बिजली का कहर: वज्रपात से एक महिला समेत तीन की मौत

दुमका, एजेंसी। जिला के रामगढ़ प्रखंड में आज मंगलवार को हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में एक महिला सहित कुल तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

दरअसल, रामगढ़ प्रखंड के गिदबोना गांव में धान रोपनी के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरे से 20 वर्षीय आलतामुनी मरांडी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के समय वह अपने पति राजेंद्र मुर्मू और चार वर्षीय बच्चे के साथ खेत में धान रोप रही थी। इसी बीच अचानक तेज बारिश होने लगी और उनपर आकाशीय बिजली गिरी। इस हादसे में आलतामुनी के पति और बच्चा भी घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं दूसरी ओर रामगढ़ थाना के रनबहियार पंचायत के खुदी मेरखो गांव में वज्रपात ने एक

और परिवार की खुशियां छीन लीं। 30 वर्षीय बाबूलाल हेंब्रम की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बाबूलाल अपनी मां के साथ खेत में काम करने गए थे। कुछ समय बाद उनकी मां घर लौट आई, जबकि बाबूलाल खेत में ही काम करते रहे। इसी दौरान लगभग दो घंटे तक लगातार हुई भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली उन पर गिर पड़ी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही दुमरजोर गांव में बारिश के दौरान हुए वज्रपात से घर के बाहर खड़े रोहित कुवर (30 वर्ष) की मौत हो गई।

दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के आलूवाडा गांव में भी आज मंगलवार की शाम वज्रपात से दो महिला बबिता देवी और चिंता देवी घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। चिकित्सकीय देखरेख के बाद दोनों की स्थिति फिन्लहाल सुरक्षित बताई जा रही है।

रांची में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में जेलकेएम का धनबाद में धरना

धनबाद, एजेंसी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने धनबाद के मेमको मोड़ स्थित शहीद मर्नोद नाथ मंडल की प्रतिमा के पास एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में दुमरी विधायक जयराम महतो समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की।

इस मौके पर दुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेलकेएम उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह धरना छात्रों के हौसले को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। यदि सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो पार्टी रांची पहुंचकर विधानसभा के समक्ष भी व्यापक आंदोलन करेगी।

विधायक जयराम महतो ने आरोप लगाया कि परीक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य की एजेंसियों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच केद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की भी मांग की।

धरना-प्रदर्शन के दौरान जेलकेएम कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन का दायरा पूरे झारखंड में बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि युवाओं के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।



झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्या ने की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पोषण आहार वितरण की समीक्षा, शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

साहिबगंज।साहिबगंज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा को लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष -सह- सदस्या श्रीमती शबनम परवीन की अध्यक्षता में साहिबगंज परिसदन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अंतर्गत खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, कल्याण एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आयोग को प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करते हुए 15 दिनों के भीतर अनुपालन प्रलिवेदन उपलब्ध कराया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती शबनम परवीन ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर एवं



गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न और अन्य निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि किसी स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उनका त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। समीक्षा बैठक से पूर्व प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्या ने राजमहल प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने

बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषण आहार, केंद्रों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति तथा अभिलेखों के संधारण का अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में जहां आवश्यक सुधार की आवश्यकता पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इसके उपरांत उन्होंने राजमहल प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का भी निरीक्षण किया तथा

मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन तैयार किए जाने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए गए। परवीन ने कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभुकों तक बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लाभुकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष -सह- सदस्या शबनम परवीन सदर अस्पताल में स्थित कुपोषण उपचार केंद्र एवं विभिन्न जन वितरण दुकानों का भी निरीक्षण किया गया एवं निर्देश दिया गया कि लाभुकों को समयसमय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष -सह- सदस्या शबनम परवीन सदर अस्पताल में स्थित कुपोषण उपचार केंद्र एवं विभिन्न जन वितरण दुकानों का भी निरीक्षण किया गया एवं निर्देश दिया गया कि लाभुकों को समयसमय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष -सह- सदस्या शबनम परवीन सदर अस्पताल में स्थित कुपोषण उपचार केंद्र एवं विभिन्न जन वितरण दुकानों का भी निरीक्षण किया गया एवं निर्देश दिया गया कि लाभुकों को समयसमय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के बाद स्टेशन जा रहे कांवरियों को कार ने मारी टक्कर, दो घायल

देवघर, एजेंसी। श्रावणी मेला के दौरान मंगलवार देर शाम बेलाबागान स्थित फॉरेस्ट ऑफिस के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार दो कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार से दो कार्टन अंग्रेजी शराब और एक कार्टन बीयर बरामद की है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार, घायल कांवरियों की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के मझार गांव निवासी राम बाबू भगत और राजन कुमार के रूप में हुई है। दोनों अपने पांच साथियों के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद ऑटो से जसीडीह रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस जांच के दौरान कार से दो कार्टन अंग्रेजी शराब और एक कार्टन बीयर बरामद हुई। नगर थाना पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले को जांच की जा रही है। श्रावणी मेला क्षेत्र में शराब बिक्री पर प्रतिबंध है। झारखंड सरकार की ओर से मेला क्षेत्र में शराब बिक्री पर रोक लगायी गयी है। ऐसे में कार से बड़ी मात्रा में शराब और बीयर बरामद होने के बाद सवाल उठने लगे है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहाँ ले जायी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, कार में बरामद शराब को देवघर कॉलेज के समीप ले जाने की योजना थी, जहां मेला क्षेत्र में अवैध बिक्री की आशंका जतायी जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

आधी रात को रांची में उत्पात, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़े, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

रांची, एजेंसी। राजधानी के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया. बदमाशों ने निजाम नगर स्थित मोती मस्जिद रोड और मक्का मस्जिद रोड पर खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनके शीशे चकनाचूर कर दिए. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में लगी हुई है. हिंदपीढ़ी के रहने वाले इमरान के कार को भी निशाना बनाया गया है. इमरान के कार के शीशे को भी तोड़ डाला गया है. उन्होंने बताया की सोमवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया. क्षतिग्रस्त वाहनों में कई कंपनियों के वाहन शामिल हैं. बदमाशों ने एक-एक कर कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

घटना का पता मंगलवार सुबह तब चला, जब वाहन मालिक घरों से बाहर निकले. अपनी गाड़ियों की टूटी हुई हालत देखकर लोगों के होश उड़ गए. देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. तोड़फोड़ की इस घटना में एक डीएसपी स्तर के अधिकारी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है, लगातार कई वाहनों को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी है.

सूचना मिलने के बाद हिंदपीढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के पहचान की कोशिश कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान कर उनपर कारवाही की जाए. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना को किसी एक व्यक्ति ने अंजाम दिया या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है. हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी अरुण महता ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

रिम्स कर्मों की दोहरी नियुक्ति मामले में विभाग हाइकोर्ट को भेजेगा रिपोर्ट

रांची, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स के पूर्व निदेशक डॉ. राजकुमार के पुत्र ऋषभ कुमार की कथित दोहरी नियुक्ति के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ायी है. इस मामले में रिम्स प्रबंधन विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है. प्रबंधन द्वारा तैयार रिपोर्ट को जल्द ही हाइकोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा. इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है यदि यह पुष्टि होती है कि निर्धारित पद से बिना इस्तीफा दिए ही किसी दूसरे संस्थान में योगदान दे रहे थे तो उन पर सेवा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

जानकारी के अनुसार ऋषभ कुमार रिम्स के मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एमएचए) विभाग में ट्यूटर के पद पर कार्यरत थे. रिम्स के अपर अधीक्षक ने इस मामले पर कहा कि ऋषभ औपचारिक इस्तीफा दिये बिना ही छुट्टी लेकर लखनऊ के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक एवं डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूप में योगदान दे रहे थे.

वहीं मामले में रिम्स प्रबंधन का कहना है कि अब तक उनका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है. सूत्रों के अनुसार मामला पहले से ही झारखंड हाइकोर्ट में लंबित है, इसलिए रिम्स प्रबंधन अब पूरे घटनाक्रम और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अदालत को सौंपने की तैयारी में है.

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है. अदालत में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही तय होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी. इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि कर्मचारी की वर्तमान सेवा स्थिति क्या है और प्रबंधन की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गयी है.

कड़ी सुरक्षा के बीच पथरा पहुंची गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा, शव देखते ही हुई भावुक

पलामू, एजेंसी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. इसी बीच जेल में बंद उसकी पत्नी रिया सिन्हा पैरोल पर भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पलामू जिले के हट्टेनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा गांव स्थित ससुराल पहुंची. इस दौरान घर परिसर में रखे पति के पार्थिव शरीर को देखते ही रिया सिन्हा उससे लिपटकर और दहाड़ मचकर रोने लगी. वहीं, सुजीत सिन्हा के 12 साल के पुत्र अश्वत कुमार सिन्हा ने भी पिता के शव को देखकर फूट-फूटकर रोना शुरू कर दिया. मां-बेटे के इस मार्मिक दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद रिश्तेदारों और ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं. रिया सिन्हा के जेल से आने की सूचना मिलते ही उसके आवास पर आसपास के क्षेत्रों के अलावा स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. जैसे ही रिया सिन्हा पुलिस कस्टडी में पुलिस वाहन से उतरी, सभी की निगाहें उसकी ओर टिक गईं.

संत रविदास की 650वीं जयंती पर प्रदेश भाजपा ने शुरू किया समरसता संकल्प अभियान

काशी की पवित्र मिट्टी पहुंची जिलों तक

रांची, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर झारखंड सहित देशभर में समरसता संकल्प अभियान चला रही है. इसके तहत मंगलवार को रांची के कार्निवल बैक्विट हॉल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर 29 जुलाई को काशी से संत रविदास जी की जन्मस्थली से लाई हुई मिट्टी को झारखंड के सभी सांगठनिक 30 जिलों में भेजा गया.

समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया: राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम: इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनत



पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज कई राष्ट्रीयरोधी ताकतें भारत को भाषा, धर्म, जाति के नाम पर लड़वाने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लिए समरसता का काम

करने वाले वे सभी महापुरुष, संत, महात्मा, महर्षि हम सबके लिए पूजनीय हैं. उन्होंने बताया कि सन 1433 ई में जब भारत पर मध्यकाल का वर्चस्व था

उस वक़्त संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ. करने वाले वे सभी महापुरुष, संत, महात्मा, महर्षि हम सबके लिए पूजनीय हैं. उन्होंने बताया कि सन 1433 ई में जब भारत पर मध्यकाल का वर्चस्व था उस वक़्त संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ.

रांची/ आसपासमिसिर के बाद बड़ा झटका: 15 लाख का इनामी नक्सली मदन महतो पत्नी सहित गिरफ्तार, कुख्यात रवि सरदार भी हत्ये चढ़ा

रांची, एजेंसी। झारखंड में नक्सलियों का अंतिम अध्याय भी लगभग खत्म होने चला है. सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 15 लाख का इनामी मदन महतो, 5 लाख का रवि सरदार और 2 लाख की इनामी मीना, जो मदन महतो की पत्नी है, को गिरफ्तार कर लिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. गिरफ्तार नक्सलियों के पास से तीन एक-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं. झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है. सरायकेला-खरसावां जिले में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने कुल 22 लाख रुपये के इनामी तीन हार्डकोर माओवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार माओवादियों में 15 लाख रुपये का इनामी मदन महतो, 5 लाख रुपये का इनामी रवि सरदार तथा मदन महतो की पत्नी और 2 लाख रुपये की इनामी महिला माओवादी मीना शामिल हैं.

बंगाल में धान रोपाई शुरू, लेकिन अब तक नहीं पहुंची डीवीसी नहरों में पानी

बर्धमान/पानागढ़ , एजेंसी। बंगाल में अमन धान की रोपाई का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) की नहरों में पर्याप्त पानी नहीं होने से पूर्व बर्धमान जिले के विस्तृत कृषि क्षेत्रों के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं. दूसरी ओर, मानसून की बारिश भी उम्मीद के मुताबिक नहीं होने से खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है. इसका सीधा असर धान की रोपाई पर पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि अमन धान की खेती के लिए

यह सबसे महत्वपूर्ण समय है. यदि समय रहते डीवीसी की नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, तो बड़ी संख्या में खेतों में रोपाई अधूरी रह जाएगी और फसल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा. बारिश नहीं होने के कारण कई किसान मजबूरी में डीजल और बिजली से चलने वाले महंगे पंपों के जरिए सिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि पहले से ही बढ़ती उत्पादन लागत किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है. स्थानीय किसान गोविंद रूईदास, हारूल शेख आदि का कहना है कि हर साल अमन की खेती काफी हद तक डीवीसी की नहरों के पानी पर निर्भर रहती है. ऐसे में नहरों में पानी की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. यदि जल्द पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, तो हजारों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है और इसका असर पूरे खरीफ सीजन की कृषि उपज पर पड़ सकता है.



दिल्ली से झारखंड की किशोरी का रेस्क्यू, आधार में जन्मतिथि बदलकर छह साल तक बनाया बंधक

रांची, एजेंसी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला की एक किशोरी को मानव तस्करी के चंगुल से छह वर्ष बाद मुक्त कराया गया है. नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाई गई पीड़िता को संयुक्त अभियान के तहत सकुशल रेस्क्यू किया गया. इस कार्रवाई को चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मिशन मुक्ति फाउंडेशन और रेस्क्यू टीम ने मिलकर अंजाम दिया. इस मामले में मानव तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जिसमें दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, जबरन घरेलू काम, बाल श्रम और जबरन विवाह जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं.

जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की रहने वाली किशोरी करीब छह वर्ष पहले लापता हो गई थी. आरोप है कि उसे नाबालिग रहते झारखंड से दिल्ली ले जाया गया, जहां उससे घरेलू काम कराया गया. बाद में उसे मुंबई भेज दिया गया और अंततः एक लाख रुपये में एक अज्ञात पंजाबी व्यक्ति को बेचकर जबरन उसकी शादी करा दी गई. इस दौरान उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.

रेस्क्यू के बाद काउंसिलिंग में पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई. उसने बताया कि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाता रहा और वर्षों तक शोषण सहना पड़ा. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पीड़िता के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग दिखा दिया था. पुलिस का मानना है कि यह फर्जीवाड़ा मानव तस्करी और जबरन विवाह को वैध दिखाने के उद्देश्य से किया गया था. अब दस्तावेजों में की गई इस कथित हेराफेरी की भी विस्तृत जांच की जा रही है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना में मानव तस्करी,

धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. प्रारंभिक जांच में गुमला निवासी प्रतिमा गुप्ता, महेमत गुप्ता, विशाल गुप्ता, मनीष भारती और मीना देवी के नाम सामने आए हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार दिल्ली के राहिणी स्थित राम विहार



इलाके से संचालित एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पीड़िता को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया था. अब एजेंसी की गतिविधियों और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है.

यह रेस्क्यू अभियान झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल के निर्देशन और समन्वय में चलाया गया. विभिन्न राज्यों की एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित कर पीड़िता

को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक पीड़िता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तारे एक बड़े मानव तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं.

झारखंड सरकार ने पीड़िता को कानूनी सहायता, काउंसिलिंग और पुनर्वास उपलब्ध



कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मानव तस्करी के खिलाफ झारखंड सरकार की ‘जिरो टॉलरेंस’ नीति के तहत पूरे नेटवर्क की पहचान कर इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस मामले में आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबनी थाना क्षेत्र के कर्मासोल (चारण) गांव का रहने वाला है. झारखंड पुलिस ने उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. मदन महतो लंबे समय से झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जंगलमहल, बेलपहाड़ी, दलमा और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय रहा है.

संगठन के भीतर वह हथियारबंद दस्तों के संचालन, सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों की योजना बनाने, नए कैडरों की भर्ती और माओवादी नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. जांच एजेंसियों के अनुसार, उसका सबसे ज्यादा संबंध एक करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी असीम मंडल उर्फ आकाश के प्रभाव वाले नेटवर्क से रहा है.

मदन महतो की पत्नी मीना (मिना) भी प्रतिबंधित माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य रही है. झारखंड पुलिस ने उस पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. मीना झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जंगल क्षेत्रों में

सक्रिय रही है. संगठन में वह संदेश पहुंचाने (कूरियर), लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने, दस्तों की गतिविधियों में सहयोग देने और सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिशों में शामिल रहने के आरोपों के कारण वांछित रही है. वह भी असीम मंडल उर्फ आकाश के प्रभाव वाले माओवादी नेटवर्क से जुड़ी रही है.

रवि सरदार प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का रीजनल कमिटी सदस्य और कमांडर है. झारखंड पुलिस ने उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. रवि सरदार मुख्य रूप से दलमा, कोल्हान, सारंडा तथा झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा के जंगलों में सक्रिय रहा है. एजेंसियों के अनुसार, वह शीर्ष माओवादी नेताओं मिसिर बेसरा और असीम मंडल उर्फ आकाश के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बनाने, आईईडी बिछाने, नए कैडरों की भर्ती करने और संगठन के विस्तार की गतिविधियों में शामिल रहा है. वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए वांछित रहा है.

जामताड़ा, बोकारो, पलामू और गढ़वा में मनाई गई शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि, गुरुजी दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

जामताड़ा/बोकारो, एजेंसी। राज्य के सभी जिलों में दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई. इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान नेताओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों और आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया.

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रथम पुण्यतिथि पर जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं विभिन्न आदिवासी संगठन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. गुरुजी के सम्मान फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया. साथ ही शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्थल का अनावरण भी किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौजूद रहे.

जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तीन दिवसीय स्वर्णीय शिबू सोरेन फुटबॉल टूर्नामेंट



प्रतियोगिता खेल का शुभारंभ किया गया. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा इंदिरा चौक पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में स्पीकर और मंत्री ने भाग लिया. इस दौरान स्पीकर और मंत्री ने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु प्रतिमा स्थल का अनावरण किया. इस मौके पर झारखंड

विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने शोषण मुक्त समाज और झारखंड राज्य के निर्माण में गुरुजी के त्याग, बलिदान और संघर्ष की गाथा को सुनाते हुए कहा कि गुरुजी झारखंड के गरीबों के आवाज थे. उन्होंने गुरुजी के लिए उनके सम्मान में केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की मांग की. झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि वह गुरुजी को पद्म भूषण दिए जाने से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि गुरुजी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए.

झारखंड छात्र आंदोलन: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को भेजा ईमेल, कहा- परीक्षा की सीबीआई से कराएं जांच

जमशेदपुर, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन अब तूल पकड़ने लगा है. यह आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रह गया है, विपक्ष भी इस आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. जमशेदपुर के बिस्पुर स्थित सर्किट हॉउस में मीडिया से बातचीत के दौरान रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के छात्र आंदोलन की दुर्दर्शा देखकर मन व्यथित है. वहां न पानी की व्यवस्था है, न टेंट का परमिशन दिया गया है.

रघुवर दास ने कहा कि छात्र आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीतिक की शुरुआत की है. इसलिए वे छात्र आंदोलन के दर्द को समझते हैं. उन्होंने इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ई-मेल लिखा है, जिसमें कोई राजनीतिक मंश नहीं है. लेटर में कहा गया कि इस मामले को दलगत भावना से अलग हट कर देखें, छात्रों से सीधी बात करें और उनकी मांग के अनुरूप मामले की सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि जिस तरह से छात्र आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि यह जनआंदोलन बन जाए और सरकार को नुकसान हो.

रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस, सपा, आरजेडी, आप, जेएमएम और वाम दल ने जंतर-मंतर में छात्र आंदोलन को समर्थन दिया था. लेकिन इसमें से किसी ने भी झारखंड के छात्रों का समर्थन नहीं दिया. विपक्ष ने हथश्रद्ध परीक्षा को लेकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए एक करोड़ मुआवजे की मांग की. लेकिन हेमंत सरकार के कार्यकाल में उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान 19 अभ्यार्थी की मौत पर चुप हैं. रघुवर दास ने प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी से अपील की है कि वे बिरसा मुंडा की धरती पर आएँ और उत्पाद सिपाही बहाली में हुई मौत के लिए भी एक करोड़ दिलावे का काम करें. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेएससीसी, सीजीएल में बड़ा घोटाला हुआ है. उनके कार्यकाल में 1,33,000 बहाली हुई, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई. लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से पेपर लीक और अनियमितता हो रही है. अब सरकार को सचेत हो जाना चाहिए. बिहार, मध्यप्रदेश और गुजरात में हुए उपचुनाव परिणाम पर रघुवर दास ने कहा कि बिहार और मध्यप्रदेश में असफलता मिली है. पार्टी इस पर गहन मंथन कर रही है कि आखिर कहाँ चूक हुई है. वहीं, जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा संचालित जेएफसी बंद करने मामले में रघुवर दास ने कहा कि सिर्फ स्टील उत्पादन ही नहीं हर क्षेत्र में टाटा की अलग पहचान है. जेएन टाटा के सपनों के शहर से खेल जगत में कई खिलाड़ियों को पहचान मिली है. उन्होंने कहा कि जेएफसी बंद करने के मामले में टाटा प्रबंधन से बात की जाएगी.



वे स्वामी संत रामानंद स्वामी जी के शिष्य बने और अपने क्षेत्रीय भाषा में दोहों और संदेशों के माध्यम से अपने धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया. उन्होंने अपनी लेखनी से न सिर्फ लोगों के मन में भक्ति भाव पैदा किया बल्कि देशभक्ति को भी बढ़ाने का प्रयास किया. उस वक़्त पूरा भारत छुआछूत और समाज में हुए बंटवारे के दंश को झेल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जात-पात को खत्म करने और समरसता बनाए रखने की पहल की.

राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि संत रविदास की वाणी सुनने राजा, रानी, संत, महात्मा, तपस्वी, सभी लोग आते थे. उन्होंने बताया कि मध्यकाल में भारत में कई ऐसे संत हुए जिनके द्वारा समाज की समरसता को बनाए रखने की सकारात्मक पहल की गई.

समरसता संकल्प अभियान राज्य के हर गांव में जायेगा-बाबूलाल: समरसता संकल्प अभियान कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला की टोली कलश को लेकर गांव गांव तक जाएंगे. यह हमारे लिए गर्व का विषय है. हम कार्यक्रम को भव्य रूप से करेंगे और समाज के हर वर्ग तक इस कलश को पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि देश में आज जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमें आपस में लड़ा कर तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, इसके लिए जरूरी है कि हम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बताए संदेशों और उनकी वाणी का अनुसरण कर जीवन में उतारें. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन षडयंत्रकारी लोगों के खिलाफ लड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत के निर्माण के साथ समाज को एक साथ जोड़ने का काम भी कर रही है.

आध्यात्मिक जगत से दुनिया को अवगत कराया: पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा: इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का यह देश आज के समय भारत के लिए पुनर्जागरण का है. हमारे देश में कई ऐसे संत हुए जिनके मार्गदर्शन से हमने आध्यात्मिक जगत से दुनिया को अवगत कराया है इसलिए भारत हमेशा से पूरे विश्व के लिए ज्ञान की धरती रही है. आज भी कई विदेशी भारत को समझने के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि 29 जुलाई से शुरू हुई और 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले इस समरसता संपर्क अभियान को हम सब मिलकर पूरा करेंगे.

दो जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने पूरे बिहार के लिए जारी किया अलर्ट

पटना, एजेंसी। बिहार में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है. सुपौल और अररिया के लिए भारी बारिश का अर्रिज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, बेगूसराय, किशनगंज समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है.

नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब सीमावर्ती जिलों में दिखने लगा है. अररिया में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. पलासी प्रखंड के वार्ड-03 में घरों में पानी घुस गया है. गांव को जोड़ने वाला चबरी पुल भी पानी में डूब गया है. प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है.

मौसम चेतावनी: बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग पटना ने 5 अगस्त 2026 के लिए पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की तरफ से जारी जिलावार अलर्ट मैप के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना है. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

आईएमडी के अनुसार, बिहार का कोई भी जिला ग्रीन जोन में नहीं है. सभी जिले येलो अलर्ट के दायरे में हैं. इसका मतलब है कि मौसम सामान्य नहीं रहेगा और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि फिलहाल किसी जिले के लिए अर्रिज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम अचानक बदल सकता है.

मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत उत्तर बिहार के जिलों में बादल छाने, रुक-रुक कर बारिश होने और कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका जताई गई है. किसानों और खुले मैदान में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

बिहार के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक

पटना, एजेंसी। बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉ. डीवाई पाटिल का मंगलवार को मुंबई में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे. राज्यपाल पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनका बिहार से जुड़ाव बना रहा. वे कई बार बिहार आए और यहां एक स्कूल की भी स्थापना की थी.

बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैय्यद अता हसनैन ने शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल का निधन सांजनीक जीवन, शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र के लिए अमूर्णीय क्षति है. उन्होंने कहा कि डॉ. पाटिल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके कार्यों को लंबे समय तक याद किया जाएगा.

बिहार में मिली यूपी की डॉसर मुस्कान की लाश, 6 साल से आर्केस्ट्रा में कर रही थी काम

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित चतुर्भुज स्थान शुक्ला रोड में मंगलवार को एक डॉसर का शव घर में मिला. नगर थाना पुलिस और टाउन एसडीपीओ-1 सुरेश कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की. पुलिस ने मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी 21 वर्षीय सरिता पाल उर्फ मुस्कान के रूप में की है. नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष रविकांत दुबे ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतका पिछले करीब पांच-छह वर्षों से इस इलाके में रहकर आर्केस्ट्रा में डॉस का काम करती थी. वह एक महीने पूर्व ही शुक्ला रोड में रुखसाना नामक महिला के मकान में किराए पर रहने आई थी.

अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षक को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना, एजेंसी। अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी भेदभाव ठीक नहीं है. समान स्थिति वाले कर्मियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता.

पटना हाईकोर्ट का फैसला: जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने एक साथ तीन रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अपने 29 पन्ने के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 2006 के नियम लागू होने के पूर्व आवेदन दिया था लेकिन राज्य सरकार ने 17 नवंबर, 2003 और 16 अप्रैल, 2005 को लागूए एफ प्रतिबंध के कारण उनके मामलों पर विचार नहीं किया. बाद में जिला अनुकंपा समिति ने 1 जुलाई, 2006 के बाद इनके नाम की अनुशंसा तृतीय वर्ग पद के लिए की. इसके बाद इन्हें प्रखंड/नगर शिक्षक के पद पर नियत वेतन पर नियुक्त कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने नियत वेतन को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनींती दी. उनका कहना था कि उनके पिता की मृत्यु 1जुलाई, 2006 से पहले हुई थी, इसलिए उनके मामले में उसी समय के लागू नियमों के अनुसार विचार होना चाहिए, न कि अनुशंसा की तारीख के समय लागू नियमों के तहत होना चाहिए. अनुकंपा पर नियुक्ति शिक्षक को राहत: उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा समिति की अनुशंसा एक प्रशासनिक और आकस्मिक कार्य है। इसमें देरी के लिए मृत कर्मचारी के आश्रितों को दंडित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार के 07 मार्च, 2019 के पत्र संख्या-336 को मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण करार देते हुए उसे रद्द कर दिया. अदालत ने हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कहा कि आवेदकों को इससे वंचित रखना समानता के अधिकार के खिलाफ है.

नियमित वेतनमान देने का आदेश: इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आवेदकों को नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया. साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को नियमित वेतनमान सहित अन्य सभी लाभ देने के बारे में तीन माह के भीत कार्रवाई करें.

जदयू में राजपूतों को तवज्जो, आनंद मोहन के बयानों के बाद संगठन और मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी

पटना, एजेंसी। बिहार की प्रमुख सत्ताधारी दल जदयू में इन दोनों राजपूत नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. नए राजपूत नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया जा रहा है. आनंद मोहन के लगातार आ रहे बयान के बाद पार्टी का ध्यान राजपूत नेताओं पर गया है. सुमित सिंह को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं लेसी सिंह को फिर से मंत्री बनाया गया है.

राणा रणधीर सिंह फिर से हुए शामिल: विधानसभा चुनाव के समय नाराज होकर जदयू छोड़ने वाले राणा रणधीर सिंह, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान को पार्टी में शामिल कराया गया है. ऐसे कई नेताओं की आने वाले दिनों में पार्टी में एंट्री कराई जा सकती है. हालांकि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जदयू को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो लोग जदयू के समाप्ति की बात कर रहे थे आज खुद उनकी क्या स्थिति है इसे देखना चाहिए.

बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा थे आनंद मोहन: विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 34 सीटों पर राजपूत प्रत्याशियों की जीत हुई थी और इसमें से 33 एनडीए के विधायक बनें. जब सरकार बनी तो कई राजपूत नेताओं को जगह भी दी गई लेकिन आनंद मोहन अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा हो गए और विरोध का झंडा उठा लिया. जदयू नेताओं पर कई आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि सरकार बनाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका है तो सरकार में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी पड़ेगी.

कई राजपूत नेताओं को खास जिम्मेदारी: आनंद मोहन के लगातार बयान के बाद भी एनडीए ने इन बातों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया. हालांकि चेतन आनंद को जदयू राज्य मंत्री के बराबर दर्जा जरूर दिला दिया. वहीं लेसी

बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, सी-4 कोच का कांच क्षतिग्रस्त

मोतिहारी, एजेंसी। पूर्वी चंपारण में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई. सुगौली स्टेशन के पास चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक कोच का शीशा टूट गया. हालांकि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 26501 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार की शाम अपने निर्धारित समय पर पाटलिपुत्र से चलकर बापूधाम मोतिहारी होते हुए आगे की ओर जा रही थी. शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर ट्रेन सुगौली स्टेशन से रवाना हुई.

कोच सी-4 क्षतिग्रस्त: स्टेशन से आगे बढ़ते ही अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी कर दी. पत्थर सीधे सी-4 कोच पर लगा, जिससे कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद यात्रियों में कुछ डर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत

बिहार में पिता ने 6 साल के बेटे को मार डाला, धारदार हथियार से गला रेटा

नवादा, एजेंसी। बिहार के नवादा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार इलाके में सोमवार को एक पिता पर अपने ही छह वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि स्वजनों का री-रोकर बुरा हाल है. परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाता था पिता: मृतक की पहचान अंदर बाजार निवासी आजाद कुमार (6 वर्ष) के रूप में हुई है. उसकी मां मुन्नी देवी (34) ने बताया कि उनके पति सुधीर गोंस्वामी वर्षों से परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे. वे न तो बच्चों के पालन-पोषण का खर्च उठाते थे और न ही कोई काम-धंधा करते थे. उल्टे शराब पीकर घर आते थे, मारपीट करते थे और घर में रखे सामान तक को बेच देते थे.

डायल-112 की मौजूदगी में हुआ था समझौता: मुन्नी देवी ने बताया कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह कई बार मायके जहानाबाद चली गई थीं. करीब दो महीने पहले भी पति की मारपीट से तंग आकर कारण वह मायके में रह रही थीं. महिला के अनुसार, दो-तीन दिन पहले डायल-112 पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था. समझौते के बाद सुधीर गोंस्वामी अपने बेटे आजाद को अपने साथ ले गया था.

मासूम पर धारदार हथियार से हमला: आरोप है कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे जब आजाद खेल रहा था, तभी आरोपी पिता ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

मां पर था पूरे परिवार का जिम्मा: मुन्नी देवी ने बताया कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. वह गांव-गांव घूमकर चुड़ी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की सामग्री बेचकर अपनी तीन बेटियों खुशी कुमारी, पूजा कुमारी और ज्योति कुमारी और इकलौते बेटे आजाद कुमार का भरण-पोषण करती थीं. उन्होंने बताया कि पति से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी. कई बार समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. घटना की सूचना मिलते ही कादिरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत भी जुटाए हैं. वहीं थानाध्यक्ष अवध किशोर प्रसाद ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि लगातार छापेमारी कर घटना के कुछ ही घंटों के बाद फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई.



सिंह को भी मंत्री बनाया गया और मनजीत सिंह को भी जिम्मेदारी दे दी. दूसरी तरफ चुनाव हारने वाले सुमित सिंह को भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई.

पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी: आनंद मोहन के कार्ड के रूप में कई नेताओं को पार्टी में तवज्जो मिलने लगी. एमएलसी संजय सिंह की भी पूछ होने लगी. वहीं विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले अब कई नेताओं को शामिल भी कराया जा रहा है. अभी हाल ही में राणा रणधीर सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान को भी शामिल कराय गया है.

राजपूत नेताओं को कयों मिल रही तवज्जो: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है राजपूत नेताओं को तवज्जो इसलिए मिल रही है क्योंकि आनंद मोहन



की बात यह रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी और ट्रेन बिना किसी बाधा के अपनी निर्धारित यात्रा पर आगे बढ़ गई.

सुरक्षा बल सक्रिय: घटना की सूचना मिलते ही बापूधाम मोतिहारी रेलवे सुरक्षा बल सक्रिय हो गया. आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास के लोगों में शुक्ताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें

जल्द गिरफ्तार किया जा सके. अज्ञात लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जांच के सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है. दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.' -

भरत प्रसाद, थाना प्रभारी, मोतिहारी आरपीएफ

सुरक्षा में सहयोग की अपील: थाना प्रभारी ने लोगों से भी अपील की कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें और ऐसी किसी भी संधिध गतिविधि की जानकारी तुरंत आरपीएफ को दें. गौरतलब है कि बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ द्वारा समय-समय पर रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ट्रेनों पर पत्थर नहीं फेंकने और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता रहा है.

रेलवे प्रशासन का रुख: इसके बावजूद वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.



10 रुपये के लिए बिहार में मर्डर, गोपालगंज में महिला पर टांगी से हमला.. इलाज के दौरान मौत

गोपालगंज, एजेंसी। बिहार के गोपालगंज में महज 10 रुपये के लेन देन के विवाद में एक महिला की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान किशोर मुशहर की पत्नी पान कुमारी की रूप में हुई है. घायल के बाद से गांव में डर का माहौल है. मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

10 रुपये के लिए बिहार में मर्डर : गोपालगंज जिले में महज 10 रुपये के विवाद में घायल महिला की सोमवार को गोरखपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना थावे थाना क्षेत्र के मठगौतम गांव की है. मामले में गिरफ्तार सभी अभियुक्त को पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि, शुक्रवार रात 10 रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत तक आ गई. इस झगड़े में किशोर मुशहर की पत्नी पान कुमारी (33 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गई. इस घटना के बाद परिजन घायल महिला को लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने यूपी के गोरखपुर अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन गोरखपुर में इलाज के दौरान सोमवार को महिला की मौत हो गई.

क्या सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे प्रशांत किशोर



संगठन और रणनीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे है.

वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के सामने भी चुनौती ये है कि प्रशांत किशोर के उभरते प्रभाव के साथ तालमेल कैसे बनाएये या फिर उनसे अलग राजनीतिक रास्ता अपनाएंगे. राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बना चुके कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने बिहार में चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर के पक्ष में आवाज बुलंद किया.

क्या राहुल गांधी के साथ जाएंगे: बांकीपुर ने बिहार के राजनीतिक दलों को नई दिशा भी दिखा दी है. जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में जाति-पाति, धर्म और संप्रदाय का बेरियर बाकीपुर में टूटा

अधिक 34 प्रत्याशी राजपूत वर्ग से ही उम्मीदवार चुनाव जीते हैं लेकिन आनंद मोहन के तरफ से यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है. उनके ओर से कहा जा रहा है कि राजपूतों की उपेक्षा हो रही है. अभी हाल में छोटू सिंह पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उसको लेकर भी खूब बवाल मचाया गया. पार्टी डैमेज कंट्रोल के तहत फैसला ले रही है जिससे आने वाले समय में किसी तरह का नुकसान ना हो.

जदयू को किसी से डरने की जरूरत नहीं: वहीं जदयू प्रवक्ता नराल शर्मा का कहना है कि जदयू को किसी से डर नहीं है, आखिर डरने की जरूरत क्या है. जदयू में विधायकों की संख्या आज बढ़ गई है, जदयू की ताकत लगातार बढ़ रही है. सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंच गई है. निशांत कुमार के पार्टी में आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. लोगों में जदयू की स्वीकार्यता और बढ़ी है.

जेडीयू में सभी जाति, धर्म के लोगों को जगह: मधुआरा आयोग के सदस्य अरविंद निषाद का कहना है ‘पार्टी में नीतीश कुमार के विकास पर सबको भरोसा है. पार्टी में सभी जाति, धर्म के लोगों को जगह दी जाती है, किसी खास के नाराज होने की बात ही नहीं है. ‘

बड़े राजपूत नेताओं को जदयू में जगह नहीं: कभी जदयू में वशिष्ठ नारायण सिंह राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रतिनिधित्व करते रहे. पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया लेकिन अब उम्र और स्वास्थ्य के कारण उन्हें इस बार जगह नहीं दी गई है. वहीं छोटू सिंह पर हुई कार्रवाई के बाद भी यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि राजपूत नेताओं को साइड किया जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले भी कई राजपूत नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दी गई थी.

पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल

पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल



पटना, एजेंसी। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है. जेपी गोलंबर से सीएम आवास घेराव के लिए निकले छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी. राजधानी में छात्रों का प्रदर्शन: हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. छात्र संगठनों ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के लिए रोजगार समेत कई मांगें उठाईं.

वाटर कैनन का इस्तेमाल: सबसे पहले जेपी गोलंबर के पास छात्रों को रोकने की कोशिश हुई लेकिन छात्र वहां नहीं रुके. डाक बंगला चौराहा पर भी छात्र नहीं रुके. प्रदर्शन करते हुए पटना के इनकम टैक्स पहुंचे, जहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाया. छात्रों का प्रदर्शन जब पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन करते हुए, जब पहुंचा तो पुलिस ने वहां वाटर कैनन से उन्हें रोकने की कोशिश की. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे. छात्रों की यही मांग है कि सिवान में छात्र पर एक-47 से जो गोली चलाई गई, वहां के बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए.

‘छात्रों पर गोली चलवाने वाले सिवान एसपी एवं एएसपी समेत सभी दोषी पुलिस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. गोली से घायल होनेवाले छात्रों को 50 लाख मुआवजा सुनिश्चित नहीं हो रही है. केवल पुलिस कर्मी को सस्पेंड करने से सरकार बच नहीं सकती. ‘-

बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश: तेजस्वी यादव

पटना, एजेंसी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा है. इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ईओ हत्याकांड पर भी सरकार को घेरा.

बांकीपुर उपचुनाव में हार पर बोले तेजस्वी: बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि, जनता का जनादेश स्वीकार है, लेकिन बीजेपी के प्रति जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलसी चुनाव भी हारी और विधायक का चुनाव भी. ऐसे में सम्राट चौधरी 150 दिनों में एक भी काम बनाएं, वह पूरी तरह फेल साबित हुए हैं. तेजस्वी ने कहा कि, जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनकी गलत नीतियों पर था. उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री है, जिनके 100 के दिन के अंदर बीजेपी दो बड़े चुनाव हारती है. अब लोगों का विश्वास बीजेपी की सरकार पर नहीं रहा है. 150 दिन में सम्राट चौधरी का एक काम गिना दीजिए, जो उन्होंने किया है.

है, उसने सियासी उछापटक के संकेत दिए हैं. संजय कुमार कहते हैं कि संभव है कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर एक भाजपा विरोधी ब्लॉक बनाएं और ब्लॉक को राष्ट्रीयपी आकार दिया जाए.

सम्राट चौधरी पर क्यों हमलावर हैं पीके: प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे हैं. डॉ. संजय कुमार का कहना है कि प्रशांत के बयान में भी कुटिल राजनीति है. प्रशांत किशोर को पता है कि उनके कहने से बीजेपी न तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी ना ही नया मुख्यमंत्री बनाएगी, फिर भी वह बयान दे रहे हैं. इसके मतलब यह है कि वह भी खुद को मुख्यमंत्री के समानांतर खड़ा करना चाहते हैं.

राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की रणनीति: अगर भविष्य में कांग्रेस और जन सुराज के बीच किसी मुद्दे पर राजनीतिक तालमेल बनता है, तो यह बिहार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी नया समीकरण तैयार होगा. प्रशांत किशोर की रणनीतिक समझ और राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति, दोनों की ताकतें साथ आती हैं तो विपक्षी राजनीति में एक नया प्रयोग जरूर देखने को मिल सकता है. बांकीपुर की हार या जीत के आधार पर आगे की राजनीति को लेकर कई तरह चर्चा हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं. क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर की जीत को बिहार के बाहर राष्ट्रीय राजनीति तक ले जा पाएंगे. क्या जन सुराज बिहार में तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर पाएगा. क्या बांकीपुर के नतीजे के बाद बीजेपी संगठन और बिहार सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला होता है.

संक्षिप्त

समाचार

महिला बैंक मैनेजर के चेहरे पर फेंका केमिकल, आंख में चोट

लखनऊ, एजेंसी। आलमबाग में चंदर नगर पुलिस चौकी के पास मंगलवार देर शाम सेंट्रल बैंक की महिला बैंक मैनेजर पर उकटी सवार युवक ने केमिकल फेंक दिया। इससे उनकी आंख में चोट आई। महिला भागकर निजी अस्पताल पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल जाकर उनके बयान दर्ज किए।

इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, गोमतीनगर विस्तार निवासी बैंक मैनेजर कार से घर जा रही थीं।



बैंक से कुछ दूर स्कूटी सवार 25 वर्षीय युवक ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। महिला ने कार का शीशा नीचे किया तो युवक गाली देने लगा। कारण पूछने पर उसने धमकी दी और बोतल से उनके चेहरे पर तरल पदार्थ फेंक दिया। जलन होने पर महिला निजी अस्पताल पहुंची। उन्होंने एंसिड अटेक की आशंका जताई। महिला का पति से विवाद चल रहा है। हालांकि उन्होंने पति का नाम नहीं बताया। पुलिस को तहरीर नहीं मिली है।

सीसीटीवी से सदिग्ध की तलाश -पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगले। फुटेज के आधार पर सदिग्ध की पहचान हुई है। उसकी तलाश की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल और कार से तरल पदार्थ के नमूने लिए हैं। कार में जलने के निशान नहीं मिले हैं।

नगराम में नम आंखों के साथ निकाला चेहलूम का जुलूस

लखनऊ, एजेंसी। मंगलवार को नगराम कस्बे में चेहलूम का जुलूस अकीदत और गमगीन माहौल में निकाला गया। इमाम हुसैन की याद में ताजिए जुलूस



के रूप में निर्धारित मार्गों से होकर कर्बला पहुंचे। वहां उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जुलूस के दौरान लोहा और मर्सिया पढ़े गए व मातम किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल पूरे समय तैनात रहा। थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने में पुलिस मुस्तैद रही।

सीरगोवर्धनपुर के लोगों ने गद्दे में उतरकर किया प्रदर्शन

वाराणसी, एजेंसी। जलभराव और खराब सड़क से खफा सीरगोवर्धनपुर के लोगों ने मंगलवार को गड्डे में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व बाबा साहब आंबेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या-23 स्थित तंत रविदास मंदिर मुख्य मार्ग पर सड़क से सटे कई गहरे गड्ढे लंबे समय से खुले हैं। इनमें



जलभराव होने से राहगीर इसमें गिरकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बीते 29 जुलाई को यहां वीआईपी आगमन हुआ था। उस दौरान इन गड्ढों को नगर निगम की ओर से बांस-बल्ली और हरे पदों से घेरकर ढंक दिया था। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि तत्काल मरम्मत संभव नहीं है तो सुरक्षा के लिए लगाई बल्ली न हटाई जाए लेकिन वीआईपी के जाते ही 30 जुलाई को सुरक्षा घेरा हटा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो जनता व्यापक आंदोलन करेगी। मौके पर लात बहादुर यादव, बाबूलाल, चंदन सोनकर, गोलू यादव, चंचल आदि मौजूद रहे।

जिले के 80 आंबेडकर प्रतिमाओं का होगा जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण

वाराणसी , एजेंसी। डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं व आसपास के स्थल का सुंदरीकरण होगा। जिले की सभी आठ विधानसभाओं में 10-10 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। हर एक पर 10 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति योजना के तहत प्रदेशभर में आंबेडकर की प्रतिमाओं की मरम्मत कराने और नई प्रतिमाएं बनवाने का निर्णय लिया है। प्रतिमा अगर पूरी तरह से टूट-फूट गई है तो उनके स्थान पर संगमरमर की नई मूर्ति स्थापित की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीशचंद्र दूबे ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के हर विधानसभा से 10-10 जीर्ण-शीर्ण डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं का चयन कर उनकी सूची तैयार की जाएगी। उन प्रतिमाओं की मरम्मत के बाद आसपास के स्थल का सुंदरीकरण किया जाएगा।

प्रतिमाओं के आस-पास लाइटिंग और हरियाली होगी- मूर्तियों के जीर्णोद्धार और प्रतिमा स्थल के निर्माण के साथ वहां हरियाली के लिए पौधे लगाए जाएंगे। अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए पांच फीट ऊंची बार्डर्ड्रौवॉल और रेलिंग बनाई जाएगी। फेंसिंग भी कराई जाएगी। आकर्षक लाइटिंग के साथ साइन बोर्ड लगाया जाएगा।

बरेली, एजेंसी।



गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे: बरेली से लखीमपुर तक संयुक्त सर्वे पूरा

जल्द शुरू होगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

बरेली, एजेंसी। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के लिए बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर जिले में संयुक्त सर्वे पूरा हो गया है। इन चारों जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अध्यापित अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

बरेली होकर गोरखपुर-शामली के बीच प्रस्तावित प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के लिए नवाबगंज और बहेड़ी तहसीलों के 68 गांवों समेत बरेली से लखीमपुर तक भूमि का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), राजस्व, वन विभाग ने संयुक्त सर्वे पूरा कर लिया है। अब यहां भूमि को कैपिटल थ्री-डी घोषित कर जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। बरेली के साथ ही पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में भूमि अध्यापित अधिकारी नामित कर दिए गए हैं।

जिन गांवों से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहां जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक पहले ही लगाई जा चुकी है। बरेली से लखीमपुर खीरी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण एनएचएआई की बरेली शाखा कराएगी। इनमें नवाबगंज तहसील क्षेत्र के 17 गांवों के साथ पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है, जबकि 51 गांवों में निर्माण का जिम्मा एनएचएआई मुरादाबाद शाखा को दिया गया है।

जल्द शुरू होगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया- अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त सर्वे समेत सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा चुका है। बहेड़ी के गांवों में एनएचएआई की मुरादाबाद शाखा ने संयुक्त सर्वे कराया है। उनका दावा है कि

इधर गिरा कोई, उधर कोई...जानलेवा हुए गद्दे, बारिश के बाद सड़कों का हुआ बुरा हाल

आगरा, एजेंसी। आगरा के दिव्ली रोड से हरीपर्वत चौराहा, बसई से इंद्रापुरम, इंद्रापुरम से अमर होटल तक, सुभाष पार्क से कोठी मीना बाजार और मारुति एस्टेट तक, टेढ़ी बगिया 100 फुट रोड। इन सड़कों पर मंगलवार को सुबह बारिश के बाद पैदल और दो पहिया वाहनों से निकलना मुश्किल हो गया। सीएम ग्रिड की इन सड़कों पर खुदाई के बाद मिट्टी छोड़ देने से हुए कोचड़ से फिसलन के कारण लोग पूरे दिन गिरते रहे। पैदल चलने वालों से लेकर दो पहिया वाहन सवार फिसलकर गिरे और चोटिल हो गए।

शहर की सड़कों पर बारिश के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दो पहिया वाहन चालक गिर पड़े। दूसरी ओर सीएम ग्रिड प्रोजेक्ट की पांच सड़कों के 11.67 किमी. लंबे हिस्से में कीचड़ और खुदाई के कारण लोग पूरे दिन मुश्किलों से जूझते रहे। क्षेत्रीय निवासी रमेश त्रिगुनायत ने बताया कि बेटे के साथ स्कूटी पर जा रहे थे कि अमर होटल के पास फिसलकर गिर गए। हाथ में चोट आई है।

बसई निवासी जीतू कुशवाह ने

बताया कि खुदाई के बाद सड़क पर

मिट्टी छोड़ देने से पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। कीचड़ के कारण कपड़े खराब हो रहे हैं। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना की सड़कों के निर्माण का निरीक्षण किया



गया है। ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि वह निर्माण के दौरान लापरवाही न बरते। मिट्टी हटाएं और गुणवत्ता का ख्याल रखें। कोई हादसा नहीं होना चाहिए।

सड़कों पर नगर आयुक्त को मिले गड्ढे, जलभराव- टेढ़ी बगिया से कालिंदी विहार तक सीएम ग्रिड के काम

देखने पहुंचे नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य को सड़कों पर गड्ढे मिले। यहां नाला टूटा होने से सड़क और छह गलियों में पानी भरा हुआ था। एक ओर की सड़क पर निर्माण कार्य चलने से दूसरे ओर की सड़क से आवागमन हो



रहा है। कई जगह सड़कों पर गड्ढे मिले, जिस पर नगर आयुक्त ने गड्ढे भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि निर्माण पूरा होने तक वैकल्पिक मार्ग की जिम्मेदारी उनकी है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराते रहें। इस दौरान चीफ इंजीनियर और सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम मौजूद रहे।

नाले में समा गई थी सड़क, छह मकानों में दसराें; अब 99.94 लाख से बनेगा आरसीसी का नाला

आगरा, एजेंसी। आगरा में ताम्रमहल के पास ताजगंज के तेलीपाड़ा स्थित पातीराम की बगीची से पाकटोला तक आरसीसी से नाले का निर्माण कराया जाएगा। इस पर नगर निगम 99.94 लाख रुपये खर्च करेगा। इससे जलभराव से राहत के साथ इस क्षेत्र के नाले के किनारे बने मकानों की नींव में पानी के बहाव से कटान नहीं होगा। बीते सप्ताह बस्ती के बीच से निकल रहे नाले की दीवार ढह जाने से हुए कटान के कारण सड़क समा गई थी, वही छह मकानों में दसराें आ गई थीं। वार्ड-63 तेलीपाड़ा की पातीराम की बगीची में इस घटना के बाद नगर निगम ने 99.94 लाख रुपये से आरसीसी का नाला बनवाने का प्रस्ताव बनाया है। नाले का पानी फिलहाल ड्रायवर्ट कर दिया गया है लेकिन नाले के पानी से हुए कटान के कारण छह मकानों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से उन मकानों में दसराें आ गई हैं। नगर निगम नाला बनवाने के साथ मकानों की मरम्मत भी कराए। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि ईंटों से बने नाले की जगह अब आरसीसी से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण के लिए टेंडर 3 सितंबर को खोला जाएगा। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

रिमांड पर आरोपी सिपाही को घटनास्थल ले गई पुलिस

गोरखपुर , एजेंसी। कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को बख्खस्त सिपाही अभिषेक यादव से गहन पूछताछ की। दस घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी को घटनास्थलों पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रीक्रिएशन कराया गया। करीब 6 घंटे 45 मिनट तक चली पूछताछ के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले।

हत्या में इस्तेमाल बांका (धारदार हथियार) घटनास्थल के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस सुबह करीब छह बजे कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को जिला कारागार से लेकर निकली। विवेचक सबसे पहले उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाया था। इसके बाद पुलिस टीम उसी रास्ते से होते हुए चिउटहा पुल के पास स्थित रम्रशान घाट पहुंची। वहां आरोपी से घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली गई और वादादत से जुड़ी परिस्थितियों को समझने के लिए सीन रीक्रिएशन कराया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी को उस स्थान पर भी ले गई, जहां से

बालिका का शव बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने कमरे से ही बांका लेकर निकला था। पुलिस के अनुसार, उसने स्वीकार किया कि बच्ची के विरोध और शोर मचाने से उसे पकड़े जाने का डर था। इसके बाद उसने हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए धारदार हथियार से शव को क्षत-विक्षत कर नदी में फेंक दिया।

हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के बयानों की पुष्टि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। रिमांड के दौरान पुलिस उसे पुलिस लाइन स्थित उसके सरकारी कमरे में भी ले गई। कमरे की जांच के बाद उसे सील कर दिया गया। वहां से मिले संभावित साक्ष्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा। जांच टीम अब बरामद हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से रिमांड में सामने आए तथ्यों का मिलान किया जाएगा। पुलिस ने दोपहर 12*45 बजे आरोपी को दोबारा जिला कारागार में दाखिल करा दिया।

शहादत का ये कैसा सम्मान?

शहीद की विधवा को मिली चार बीघा जमीन पर बनी

सरकारी टंकी, फसल हो रही बर्बाद

आगरा, एजेंसी। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीद की विधवा को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गांव डावली में शहीद उदय सिंह की पत्नी को आजीविका के लिए पट्टे पर मिली चार बीघा जमीन पर बनी सामुदायिक पानी की टंकी उनके लिए मुसीबत बन गई है। ओवरफ्लो होते पानी और टूटी तारबंदी के कारण फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन प्रशासन मौन है।

वर्ष 2012 में जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर आतंकियों से लोहा लेते हुए उदय सिंह शहीद हो गए थे। प्रशासन ने उनकी पत्नी मिथलेश को गांव डावली में गाटा संख्या 325/1693 में चार बीघा कृषि भूमि का पट्टा दिया था। इस जमीन पर पहले से एक सामुदायिक पानी की टंकी बनी हुई है, जिसे खेत की नाप के दौरान अलग नहीं किया गया। पीड़िता का आरोप है कि टंकी के ओवरफ्लो होने से खेत में पानी भर जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। आसपास के लोगों ने खेत की तारबंदी भी तोड़ दी है, जिससे छुट्टा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मिथलेश ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी तक गुहार लगाई है। आरोप है कि प्रधान इसे हटाने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर आईजीआरएस जांच रिपोर्ट के अनुसार, टंकी को हटाने के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर जल निगम से समन्वय स्थापित करना होगा, तभी इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। लालफीताशाही से परेशान होकर अब शहीद की पत्नी ने चेतावनी दी है कि यदि ग्राम सभा अपनी निधि से टंकी को शिफ्ट नहीं करती है, तो वह स्वमर्सिबल समेत भूमि को जोतवा देगी। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।



सड़क में अचानक हुआ 20 फीट गहरा गड्ढा, वाहनों का प्रवेश बंद; संजय प्लेस संभलकर जाएं

आगरा, एजेंसी। आगरा के हरीपर्वत चौराहे स्थित ट्रैफिक सिग्नल की स्टॉप लाइन पर सीवर मैनहोल के पास सड़क धंसने से 20 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। स्पीड कलर लैब से

हरीपर्वत चौराहे जाने वाली सड़क पर यह गड्ढा हुआ, जिससे शाम को करीब तीन घंटे तक ट्रैफिक ड्रायवर्ट करके निकाला गया। नगर निगम और वीए टेक वगैरा की टीम ने रात 9 बजे तक गड्ढे को मलबा और गिट्टियां डालकर भरा, जिसके बाद यहां से भारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया।

एमजी रोड पर हरीपर्वत चौराहे होते हुए पुरानी ईंटों की डाट तकनीक से बनी सीवर लाइन बिछी हुई है। मंगलवार शाम को यहां गहरा गड्ढा हो गया जो लगातार चौड़ा होता चला गया। यहां करीब 20 फीट गहरी सीवर लाइन और करीब 6 फीट गहरी पानी की पाइपलाइन है। सीवर लाइन में लीकेज के कारण सड़क धंसने की आशंका जताई जा रही है। जलकल के अधिशासी अभियंता संघभूषण ने बताया कि फिलहाल गड्ढा भरवा दिया है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि लाइन

कितनी क्षतिग्रस्त है। यहां काम करने के लिए ट्रैफिक ड्रायवर्जन करना होगा।

स्कूली बच्चों को होगी परेशानी- हरीपर्वत चौराहे पर मेट्रो की बैरिकेडिंग के कारण एक लेन पहले से ही कम है। अब चौराहे से पहले सीवर मैनहोल के पास लीकेज के कारण हुए गड्ढे की बैरिकेडिंग से यहां केवल एक कार निकलने की जगह है। बुधवार को स्कूलों की छुट्टी के समय जाम की आशंका है। भगवान टॉकीज से सदर जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग है, जिस पर से हर दिन लाखों लोग निकलते हैं।

वजीरपुरा, सेंट पीटर्स रोड होकर हरीपर्वत निकलेगे वाहन- एडीसीपी अलका सिंह ने बताया कि हरीपर्वत पर सड़क धंसने के बाद ट्रैफिक ड्रायवर्ट किया गया है। वाहनों को सूरसदन से कॉसमॉस मॉल होकर सेंट पीटर्स रोड, मंडी सईद खां से एमडी जैन इंटर कॉलेज होते हुए हरीपर्वत चौराहे की तरफ निकाला जा रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया है। बैरिकेडिंग भी कर दी गई है



संक्षिप्त समाचार

अब सिविक सेंटर से बाकनेर गांव तक मिलेगी सीधी डीटीसी बस, रोजाना चार फेरे लगाएगी सेवा
नई दिल्ली, एंजेंसी। मध्य दिल्ली स्थित एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर से बाहरी दिल्ली स्थित बाकनेर गांव तक नई डीटीसी बस सेवा शुरु हुई है। नई बस सेवा रुट संख्या 131 प्रातः आठ और 8:30 बजे बाकनेर गांव से निगम मुख्यालय तक आएगी और शाम को 5:45 व 6:30 बजे निगम मुख्यालय से बाकनेर गांव तक जाएगी। यह बस सिविक सेंटर से राजघाट, आइएसबीटी, मुकरबा चौक, शनि मंदिर होते हुए बाकनेर गांव तक जाएगी। सिविक सेंटर के बाहर से नेता सदन जय भगवान यादव व स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। दोनों नेताद्वय ने इस नई बस सेवा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों व दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर नरेला वार्ड समिति के उपाध्यक्ष दिनेश भारद्वाज, पार्षद राजपाल राणा व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

चार महीने पहले सीवर लाइन के लिए खोदी सड़क आज तक नहीं बनी, जलभराव और गड्ढों से राहगीर परेशान
नईदिल्ली, एंजेंसी। सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए करीब चार महीने पहले सड़क की खोदाई की गई थी। काम पूरा होने के बाद आज तक सड़क नहीं बनी है। कई जगहों पर मोटे पत्थर पड़े हैं जिनकी वजह से आए दिन ट्रफहिया वाहन चालक और राहगीर चोटिल होते हैं। हल्की वर्षा के बाद जलभराव होने से समस्या और विकट हो गई है। यह दिक्कत है संगम विहार स्थित नई बस्ती रोड देवली के लोगों की। इलाके में खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान हैं। लोगों की शिकायत है कि इसके चलते सड़क से आवाजाही मुश्किल हो चुकी है। कई बार इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। स्थानीय आरडब्ल्यूए के मुताबिक संगम विहार से देवली लिंक रोड मुख्य स्थानीय निवासी और राहगीर गुजरते हैं। मुख्य सड़क होने की वजह से इस सड़क पर पैदल चलने वालों के साथ वाहनों का भी ख़ासा दबाव रहता है। सुबह बच्चों को लेने के लिए कई स्कूली वैन निकलती हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के चलते स्कूली बच्चे और बड़े सभी परेशान हैं। सोमवार रात हुई हल्की वर्षा के बाद हालात हो चुके हैं कि लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो चुका है।। ग्रीव्स पोर्टल तक शिकायत, समाधान नहीं आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राजीव बंसल का कहना है कि चार महीने पहले सीवर लाइन डालने के लिए सड़क की खोदाई की गई थी। काम पूरा हो चुका है लेकिन आज तक इस्की मरम्मत नहीं हुई है। सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से खासी आबादी परेशान है।

दिल्ली के स्कूल में पांचवीं के छात्र से छह महीने तक होता रहा यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
नईदिल्ली, एंजेंसी। नरेला के एक सरकारी स्कूल में कक्षा पांच के छात्र के साथ स्कूल परिसर के शौचालय में पिछले करीब छह महीने तक कथित यौन शोषण होने का मामला उजागर हुआ। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस सूत्र के अनुसार, पीड़ित छात्र ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके साथ स्कूल के शौचालय में उसके ही आठ सहपाठी कथित तौर पर यौन शोषण करते थे। आरोप है कि घटना किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रहा। लेकिन 30 जुलाई को कथित रूप से फिर ऐसी घटना हुई। बाद में स्कूल में पढ़ने वाले एक अन्य बच्चे को इसकी जानकारी मिली, जिसने पीड़ित छात्र की मां को पूरे मामले से अवगत कराया। जानकारी देने वाला छात्र पीड़ित का रिश्तेदार है। इसके बाद पीड़ित के स्वजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

नई दिल्ली, एंजेंसी। नरेला के एक सरकारी स्कूल में कक्षा पांच के छात्र के साथ स्कूल परिसर के शौचालय में पिछले करीब छह महीने तक कथित यौन शोषण होने का मामला उजागर हुआ। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस सूत्र के अनुसार, पीड़ित छात्र ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके साथ स्कूल के शौचालय में उसके ही आठ सहपाठी कथित तौर पर यौन शोषण करते थे। आरोप है कि घटना किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रहा। लेकिन 30 जुलाई को कथित रूप से फिर ऐसी घटना हुई। बाद में स्कूल में पढ़ने वाले एक अन्य बच्चे को इसकी जानकारी मिली, जिसने पीड़ित छात्र की मां को पूरे मामले से अवगत कराया। जानकारी देने वाला छात्र पीड़ित का रिश्तेदार है। इसके बाद पीड़ित के स्वजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जलडमरूमध्य से किसी भी अस्थायी मार्ग में कोई बाधा नहीं

वाशिंगटन/तेहरान, एंजेंसी। होर्मुज जलडमरूमध्य से बनाए जाने वाले किसी भी अस्थायी जहाज मार्ग के लिए किसी सरकारी दस्तावेज (परमिट), मंजूरी या शुल्क की जरूरत नहीं होगी। इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर किसी एक पक्ष का नियंत्रण नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बात कही गई है।
अधिकारी ने कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य से किसी भी अस्थायी मार्ग में कोई बाधा, परमिट, मंजूरी या शुल्क नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पक्ष समुद्री मार्गों को नियंत्रित नहीं करता है और न ही किसी जहाज को इस जलडमरूमध्य से गुजरने से रोक सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को ईरान के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को खोलने को लेकर समझौता ‘आज या कल’ हो सकता है। बेसेंट ने कहा कि यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पिछले हफ्ते ईरान को दी गई धमकियों के बाद आया है।

उन्होंने ट्रंप की उस कार्रवाई को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े संभावित सैन्य अभियानों में से एक बताया। बेसेंट ने कहा, हमने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक की धमकी देते देखा। इसी वजह से हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज या कल होर्मुज

दिल्ली के ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए खुशखबरी, दारका में जल्द आवंटित होंगे 2700 फ्लैट

नई दिल्ली, एंजेंसी। दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को लंबे समय से तैयार पड़े फ्लैट आवंटित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

इसी क्रम में द्वारका स्थित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित करीब 2700 फ्लैटों की मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य के लिए सरकार ने दोबारा टेंडर जारी किया है। इससे पहले निकाला गया टेंडर निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद संशोधित प्रक्रिया के तहत नया टेंडर आमंत्रित किया गया है।

मरम्मत पर 12 करोड़ खर्च करेगी सरकार
सरकार इस मरम्मत कार्य पर लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च करेगी। फ्लैट काफी समय से खाली पड़े हैं, जिसके कारण इनमें कई स्थानों पर मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता पैदा हो गई है। निर्माण संबंधी कमियों को दूर करने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की

मरम्मत, विद्युत एवं जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने, पेंटिंग तथा अन्य जरूरी कार्य इस परियोजना के तहत किए जाएंगे ताकि फ्लैट आवंटन के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।

अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को इन फ्लैटों का आवंटन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य पहले से निर्मित, लेकिन खाली पड़े आवासों का उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके।

जेएनएनयूआरएम योजना के तहत इन फ्लैटों का

निर्माण शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि विभिन्न



कारणों से इनका आवंटन लंबे समय तक लंबित रहा। अब सरकार मरम्मत कार्य पूरा कर इन्हें शीघ्र आवंटित करने की तैयारी में है। अधिकारियों का मानना है कि इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास मिलने का रास्ता साफ होगा।

24 घंटे इंतजार के बाद मात्र 10 मिनट मिल रहा पानी

दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पेयजल संकट से लोग त्रस्त



नईदिल्ली, एंजेंसी। हम लोग 24 घंटे पानी के लिए इंतजार करते हैं और सुबह मुश्किल से 10 मिनट ही पानी की आपूर्ति होती है। पहले यह दिक्कत कभी कभार होती थी अब रोजाना की यही स्थिति है। इसे लेकर लगातार जल बोर्ड से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ। करीब ढाई हजार की आबादी बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान है। यह समस्या

देवली विधानसभा स्थित दक्षिणपुरी एक्सटेंशन स्थित डीडीए फ्लैट्स ब्लॉक-20 के निवासियों की है। लोगों में इस बात से नाराजगी है कि 600 से ज्यादा परिवार भीषण पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है।

आरडब्ल्यूए के मुताबिक इलाके में पेयजल किल्लत की समस्या लंबे समय से बनी हुई है।

सात घायलों को वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया

हादसे के बाद अस्पतालों को किया गया अलर्ट

नईदिल्ली, एंजेंसी। फूकेट से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान के साथ हादसे के कारण कई यात्री और केबिन क्रू के सदस्य घायल हो

एहूचने की सूचना पहले ही एयरपोर्ट एंथारिटी की तरफ से दी जा चुकी थी। इस वजह से यहां आपातकालीन विभाग में उनके लिए तैयारी शुरू कर



गए। विमान की लैंडिंग के बाद एम्बुलेंस की मदद से भी सात घायलों को वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इनके अलावा दो इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर और पांच को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। फोर्टिस अस्पताल में घायलों के

एक-दूसरे का हाल जानने की कोशिश कर रहे थे।

केबिन क्रू सदस्य की रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर: यहां पहुंचे घायलों में से तीन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई,

जबकि चार का इलाज जारी है। हादसे में एक केबिन क्रू की महिला सदस्य की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया।

उधर, मेदांता अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फोर्टिस अस्पताल के आपातकालीन विभाग के प्रमुख डा. उमंग ने

बताया कि दोपहर करीब साढ़े 12 बजे घटना की सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीम को अलर्ट कर दिया गया था। डाक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को तत्काल तैयार रहने के निर्देश दिए गए।

करीब एक बजे तक सभी सात घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया,

जहां बिना देरी उपचार शुरू कर दिया गया। बाकी तीन केबिन क्रू सदस्यों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। अस्पताल के अनुसार भर्ती सभी केबिन क्रू की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है।

अस्पताल में देर तक स्वजन और एयरलाइन अधिकारियों की आवाजाही भी बनी रही, जबकि मेडिकल टीम लगातार घायलों की निगरानी करती रही। डाक्टरों के मुताबिक सभी घायलों को वार्ड में भेज दिया गया है।

अस्पताल पहुंचे उड्डयन मंत्री फोर्टिस अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों से उनका हालचाल पूछा। उन्हें हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। नायडू ने कहा कि घायलों को जरूरी मेडिकल सहायता दी जा रही है। उन्होंने अस्पताल के डाक्टरों के साथ एअर इंडिया और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और निर्देश दिया कि हर दो घंटे में घायलों की स्थिति की जानकारी दी जाए।

दिल्ली पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के कार्यों में बड़ा फेरबदल, पहली बार ईएनसी संभालेंगे सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, एंजेंसी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मुख्य अभियंता जेजेआर मीणा की पदोन्नति के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में तबादले के बाद एक बार फिर विभागीय कार्यों के समन्वय और परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य आवंटन में बदलाव किया है। पीडब्ल्यूडी में चुनौतीपूर्ण माने जाने वाला सड़कों के रखरखाव का काम प्रभार पहली बार अब ईएनसी के पास आया है। इससे पहले ईएनसी इस प्रभार को अपने पास नहीं रखते थे। अस्थायी रूप से ईएनसी का काम देखने के दौरान विवेक ने इस कुछ समय के लिए अपने पास रखा था, मगर उसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया था। दरअसल इस विंग में प्रतिदिन चलने वाले सबसे अधिक काम की जिम्मेदारी रहती है। जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में इंजीनियर-इन्-चीफ (ईएनसी) का कार्यभार संभाल रहे एएसडीजी (विशेष महानिदेशक) नवीन कुमार बंसल अब एडीजी (रखरखाव एवं बागवानी) का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधान मुख्य अभियंता विवेका नंद विवेक को मुख्य अभियंता (पलाईओवर) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कार्यालय आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी की पूर्व अनुमति के बाद लिया गया है।

दिनभर में मात्र 10 मिनट ही पानी की आपूर्ति होती है। इतने कम समय में टंकी में इतना ही पानी पहुंच पाता है कि चार लोगों के परिवार की रोजाना की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है।

लोगों को दूर-दराज के इलाकों से पानी लेकर आना पड़ता है या फिर बोलतबंद पानी से काम चलाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। लोगों की मांग है कि इलाके में पानी की आपूर्ति कम से कम 30 मिनट के लिए निर्धारित की जाए जिससे लोगों को नियमित कार्यों के लिए पानी मिल सके। इस संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है।

यह परेशानी काफी समय से बनी है। महीनों पहले पानी का सप्लाई लगातार कम होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड का कहना था कि पुरानी पाइपलाइन बदलकर दिक्कत दूर की जाएगी। छह महीने पहले पाइपलाइन भी बदली जा चुकी है, लेकिन पानी की आपूर्ति में कोई सुधार नहीं है।

दिल्ली को टीबी मुक्त बनानेकी मुहिम तेज, सीएम रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों से की ‘निक्षयमित्र’ बननेकी अपील

नई दिल्ली, एंजेंसी। दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन की ओर से जनप्रतिनिधियों की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सांसदों, विधायकों, पार्षदों के साथ-साथ कॉर्पोरेट संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए और आम नागरिकों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसे जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाना होगा। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने टीबी जागरूकता पर आधारित वीडियो प्रदर्शित किया, जबकि दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने अभियान की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना पर प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने टीबी जागरूकता और निक्षय मित्र अभियान से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही पोषण सहायता, पुर्नवास और डिजिटल सहयोग व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को वार्ड और विधानसभा स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित टीबी रोगियों की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) के लक्ष्य के मुकाबले दिल्ली लगातार 95 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और पूरा उपचार मिलने पर टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें और इलाज पूरा कराने के लिए प्रेरित करें। 3,300 से अधिक सहयोगियों ने पहुंचाए 1.2 लाख पोषण किट दिल्ली सरकार के अनुसार राजधानी में अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र अभियान से जुड़ चुके हैं और उनके सहयोग से 1.2 लाख से अधिक पोषण आहार (फूड बारकेट) टीबी मरीजों तक पहुंचाए जा चुके हैं।

भारत में ही रहेगा एआई डाटा

अम्मान, एंजेंसी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र की कंपनी एंथ्रोपिक ने भारत में अपने कारोबार का विस्तार करते हुए घोषणा की है कि उसके वलाउड एआई मॉडल अब अमेजन बेडरॉक के भारतीय बुनियादी ढांचे को जरिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही वलाउड एआई का संचालन भारत में मौजूद सर्वर पर ही होगा। इसे इन-कौट्री इम्पेमेंट्स कहा जाता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ बैंकिंग, सरकारी एंजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य वित्तीयमित क्षेत्रों को मिलेगा, जहां संवेदनशील और गोपनीय डाटा का उपयोग होता है। स्थानीय सर्वर पर प्रोसेसिंग होने से डाटा देश की सीमाओं के भीतर ही रहेगा। इससे एआई आधारित एप्लीकेशन तैयार करने के दौरान डाटा रेंजिडेंसी और कानूनी अनुपालन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करना आसान होगा। एडब्ल्यूएस इंडिया के अध्यक्ष सदीप दत्ता ने कहा कि अमेजन बेडरॉक के जरिये एंथ्रोपिक के वलाउड मॉडल अब एडब्ल्यूएस के भारतीय बुनियादी ढांचे पर उपलब्ध होंगे। भारत वलाउड के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो चुका है। कंपनी का कहना है कि यह स्थानीय बुनियादी ढांचे पर होस्ट किए जाने वाले एंटरप्राइज एआई समाधानों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके वलाउड पार्टनर नेटवर्क के लिए सबसे अधिक पंजीकरण भारत से हुए हैं। इसी के तहत एंथ्रोपिक अपने पार्टनर नेटवर्क के माध्यम से 5,000 से अधिक पेशेवरों को स्थानीय एआई विशेषज्ञता विकसित करने का प्रशिक्षण देगी। भारत में एंथ्रोपिक की प्रबंध निदेशक इरिना घोष ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग होने से कंपनियों के लिए छोटे एआई पायलट प्रोजेक्ट्स से बड़े स्तर पर एआई का उपयोग करना आसान होगा।

संपादकीय

बहस के बिना कानून: लोकतंत्र में जरूरी है संवाद

संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां जनकल्याण से जुड़े मसलों पर मंथन किया जाता है और उसके निष्कर्षों के आधार पर नीति निर्माण का खाका तैयार किया जाता है। जनता की आकांक्षाओं को आकार देने और देश को लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करने में संसद की भूमिका सर्वोपरि है। आमजन की यह उम्मीद होती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं, चिंताओं एवं जरूरतों को संसद में रखेंगे और उन पर विचार-विमर्श के बाद एक सक्षम कानून या योजना बनाई जाएगी। मगर, जब संसद में व्यापक चर्चा के बिना ही किसी विधेयक को पारित कर कानून की शक्ल दे दी जाए, तो उसकी समग्र व्यावहारिकता और सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संसद के मानसून सत्र में अब तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। हाल ही में

विद्यार्थियों के आंदोलन से निकले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को व्यापक चर्चा और सुझावों के बिना ही पारित कर दिया गया और सोमवार को दो अन्य विधेयकों को भी इसी तरह से मंजूरी दे दी गई।

अहम सवाल यह है कि संविधान में संसद सत्र आयोजित किए जाने की जो व्यवस्था की गई है, क्या उसका मूल उद्देश्य पूर्ण हो पा रहा है? अगर किसी कानून या योजना को सक्षम एवं कारगर बनाने में विपक्ष की कोई भूमिका न हो, तो संसद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? इसमें दोराय नहीं कि सदन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। मगर जब विपक्ष कोई सवाल या समस्या उठाता है, तो उसका निराकरण करना सत्तापक्ष का दायित्व होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तापक्ष अपनी



जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकता। संसद के मानसून सत्र की अब तक की अवधि पर नजर डालें, तो हंगामा और कार्यवाही का स्थगन, इन्हीं दो बातों पर जोर दिया गया है।

ऐसा लगता है कि स्थगन, कार्यवाही का पर्याय बन गया है। विपक्ष नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लगातार संसद में उठा रहा है और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो जाती है। इस बीच महत्वपूर्ण विधेयक भी व्यापक चर्चा के बिना ही पारित हो जाते हैं।

संसद में बने इस गतिरोध को दूर करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप के जरिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, तो सत्तापक्ष का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश

संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 और राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक भी विस्तृत चर्चा के बगैर ही पारित कर दिए गए।

ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि संसद में अपेक्षित कामकाज न होने से उसके कीमती समय और धन की जो बर्बादी हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह दोनों पक्षों का दायित्व नहीं है कि गतिरोध को खत्म करने के लिए व्यावहारिक तौर पर गंभीरता से प्रयास किए जाएं, ताकि जन सरोकार से जुड़े मसलों पर सार्थक चर्चा और मूल्यवान सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सके। किसी भी समस्या का हल सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, फिर चाहे संसद में गतिरोध हो या सड़क के रास्ते सत्ता के गलियारों में पहुंचने वाली मांग हो।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दम

इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत भले ही चौथे स्थान पर रहा लेकिन देश के खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया, वह एक बेहतर भविष्य का संकेत है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हर अगले आयोजन में खेलों में जीत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा खड़ती जा रही है, क्षमताओं की कसौटियां ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की मांग कर रही हैं लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैदान में अपनी धमक छोड़नी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीते। ज्यादातर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी खासी चुनौती पेश की लेकिन भारोत्तोलन, जूडो और पैरा खेलों में भारत ने इतिहास रचते हुए अपनी



कामयाबी का झंडा बुलंद किया। खासतौर पर मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण और तीन रजत के साथ कुल दस पदक जीते बल्कि इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी के मैदान में अपनी सबसे कामयाब छाप छोड़ी और महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा, एक ही राष्ट्रमंडल खेल में एथलेटिक्स में एक से ज्यादा पदक जीतने वाले पहले भारतीय गुलवीर सिंह भी इस आयोजन में देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहे। अलग-अलग खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शीर्ष स्तर पर रहने वाले देशों को ठोस चुनौती दी और एक तरह से यह दर्शाया कि किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उनकी उपस्थिति को अब महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। पदकों की संख्या के संदर्भ में देखा जाएगा तो इसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धि से कम माना जाएगा। हालांकि, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस वर्ष के आयोजन में कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे कुछ खेल नहीं थे जिसमें पारंपरिक रूप से भारत का मोर्चा मजबूत रहा है। हालांकि मौजूदा उपलब्धियों और अन्य देशों के प्रदर्शन के आलोक में देखें तो भारत को अभी काफी प्रयास करना होगा लेकिन इस आयोजन में हासिल उपलब्धियां और प्रदर्शन का स्तर भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उम्मीद के वाहक हैं।

आज का कार्टून

सीजेआई प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी ने कहा छात्रों से ज्यादा पंवर बनाने वाले थे

ऐसे नेताओं से ही पाप का घड़ा जल्द भरेगा!!

आखिर क्यों पूरा नहीं कर पाते शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल

योगेंद्र योगी

शिक्षा मंत्रालय के जरिए मोदी सरकार का सारा जोर संघ को साधने में रहा है, किन्तु शिक्षा के उत्थान के लिए बजट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बजट घटता गया और विवाद बढ़ते गए। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेजी से घटी है यह हिस्सा 2013-14 में कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट ही दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। चारों शिक्षा मंत्रियों के समय में लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फ्रैकल्टी के चयन में संघ की विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक रोजगारपरक, रचनात्मक, सकारात्मक और शोधपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित मुद्दे खास स्थान नहीं ले सके। पेपर लीक के केंद्र ही नहीं राज्यों की सरकारों ने कठोर कानून बनाए हैं, सजा और जुर्माने को बढ़ाया है, किन्तु देश में जब तक मौजूद सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक चाहे कितने ही मंत्री बदल दिए जाएं, पेपर लीक की घटनाएं रुकने की कोई गारंटी नहीं है।

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इस्तीफा देने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। साल 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और धर्मेन्द्र प्रधान को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा।

पाँचवा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, हालांकि जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोदी सरकार को तय करना है कि जोशी ही पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री रहेंगे या किसी नए चेहरे की तलाश करके उसको स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जोशी भी विवादों में रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंग रेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उग्र क़ैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर जब चोतरफा सवाल उठ रहे थे, तब प्रहलाद जोशी ने इसका बचाव किया था।

सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा प्रमुख मंत्रालय रहा,

जिसकी कमान पांच अलग-अलग मंत्रियों ने संभाली वहीं, गुह, विशेश, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईएनबी) ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय हैं, जिन्हें सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं।

यही कारण है कि यहां विवाद ज्यादा हुए और अस्थिरता भी उत्पनी ही दिखती है। गौरतलब है कि आईएनबी में 12 साल के भीतर सात केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में पांच केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह जिम्मेदारी रमेश पोखरियाल 'निशंक' को मिली। मगर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान धर्मेन्द्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर-मंतर पर बैठे रहे और आखिरकार केंद्र सरकार दबाव में

का मुद्दा बन गई। मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विजन लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये जरूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीका अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज्यादा मुखर थीं, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासन में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गईं, वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मकसद से लागू हुईं। संघ का मकसद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचारधारा वाली शिक्षा-पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ मानता है कि वे मुगलों के समर्थक रहे हैं। संघ की नजर में, मुगल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। संघ पर आरोप लगते रहे कि इस एजेंडे को पूरा मोदी सरकार के जरिए कराया जा रहा है।

इसी लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार के चार शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना रहा है। 'स्मृति ईरानी को छोड़ दें, तो नवनि्युक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और धर्मेन्द्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजपेयी के जमाने में



भी संघ से आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दखल हमेशा चाहता रहा है। स्मृति ईरानी के साथ उनके नाम पर डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे।

स्मृति ईरानी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं थीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने में देरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्मृति से बहुत खुश नहीं था। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर-शराबा नहीं करता। यही कारण है कि फिलाहल संघ की पृष्ठभूमि वाले प्रकाश जोशी को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के समय इसे लागू किया गया।

शिक्षा मंत्री रहे 'निशंक की पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है, जो संघ के मकसद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि, अपने अवैज्ञानिक बयानों को लेकर भी वे विवादों में आए। उन्होंने यहां तक कहा कि चरक ऋषि ने अणु-परमाणु की खोज की थी। कॉविड के समय जेईई-नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद निशंक के खुलाफ काफ़ी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए, जहां सरकार के पक्ष में फैसला आया। हालांकि, तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से रह गए, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके समय भी आरोप लगा कि नई शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार शिक्षा पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकार दिया था।

शिक्षा मंत्रालय के जरिए मोदी सरकार का सारा जोर संघ को साधने में रहा है, किन्तु शिक्षा के उत्थान के लिए बजट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बजट घटता गया और विवाद बढ़ते गए। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेजी से घटी है यह हिस्सा 2013-14 में कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट ही दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। चारों शिक्षा मंत्रियों के समय में लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फ्रैकल्टी के चयन में संघ की विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक रोजगारपरक, रचनात्मक, सकारात्मक और शोधपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित मुद्दे खास स्थान नहीं ले सके। पेपर लीक के केंद्र ही नहीं राज्यों की सरकारों ने कठोर कानून बनाए हैं, सजा और जुर्माने को बढ़ाया है, किन्तु देश में जब तक मौजूद सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक चाहे कितने ही मंत्री बदल दिए जाएं, पेपर लीक की घटनाएं रुकने की कोई गारंटी नहीं है।

बृजभूषण के बरी होने से बदलेंगे समीकरण ?

नीरज कुमार दुबे

करीब तीन वर्षों तक देश की राजनीति, खेल जगत और मीडिया के केंद्र में रहे पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को आखिरकार दिल्ली की राजउ एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिल गई। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। वैसे बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के समर्थन में जिस तरह तमाम विपक्षी नेता खड़े हो गये थे उसके चलते यह सब कुछ शुरू से ही राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा था।

पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यदि आरोप सही साबित हुए तो वह स्वयं फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आज का दिन उनके लिए प्रसन्नता का विषय है। वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा है कि विस्तृत निर्णय मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उच्च अदालत में आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि यह मामला अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ था, जब दिल्ली के कर्नाट प्लेस थाने में छह महिला पहलवानों की शिकायत पर

एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी दौरान एक नाबालिग की शिकायत पर पाँक्सो कानून के तहत भी अलग मामला दर्ज हुआ था। जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें चार राज्यों के 22 गवाहों के बयान शामिल थे। बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए थे। पुलिस ने अदालत से पाँक्सो मामला समाप्त करने का अनुरोध किया था जिसे मई 2025 में अदालत ने स्वीकार कर लिया था। मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ

भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि



शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, स्थान और घटनाओं को लेकर कई बदलाव हुए तथा कुछ घटनाओं के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। बचाव पक्ष ने शिकायत दर्ज कराने में सात-आठ वर्ष की देरी का मुद्दा भी उठाया। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िताओं के बयान मुकदमे के दौरान लगातार एक जैसे रहे और अन्य गवाहों ने भी उनका समर्थन किया। शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेवेका जॉन ने अदालत में तर्क दिया कि शक्ति के असंतुलन और खेल संघ के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के

प्रभाव के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी स्वाभाविक थी। हालांकि, अंततः अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। उधर, इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं माना जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों के आंदोलन और बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों ने भाजपा को असहज स्थिति में ला दिया था। पार्टी को विपक्ष के लगातार हमलों का सामना करना पड़ा और अंततः कैसरराज से बृजभूषण की जगह उनके पुत्र करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया था। अब अदालत से बरी होने के बाद भाजपा के लिए यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से राहत देने वाला माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अगले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

हम आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव देवीपाटन मंडल और अवध क्षेत्र के कई जिलों में लंबे समय से माना जाता है। गोण्ड, बहराइच, बलारामपुर, श्रावस्ती तथा आसपास के क्षेत्रों में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़, सामाजिक नेटवर्क और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क रहा है। ऐसे में उनके बरी होने के बाद इन क्षेत्रों में

भाजपा की चुनावी संभावनाएं और मजबूत होने की चर्चा राजनीतिक हलकों में शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि उनके समर्थकों में नया उत्साह आएगा और इसका लाभ भाजपा उम्मीदवारों को मिल सकता है। हालांकि, इस फैसले के बाद भाजपा नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती भी उभर सकती है। माना जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक प्रभाव देवीपाटन मंडल और अवध क्षेत्र में और बढ़ेगा इसके चलते विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में उनकी राय और पसंद को भी महत्व देना पड़ सकता है। स्थानीय राजनीति में उनका प्रभाव देखते हुए पार्टी के लिए संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर एक और पहलू पर भी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते थे क्योंकि उनके विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया था। अब अदालत से राहत मिलने के बाद यह अटकलें भी तेज हो सकती हैं कि भविष्य में संगठन या सरकार में उनके परिवार की राजनीतिक भूमिका और मजबूत हो। हालांकि, इस संबंध में भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।

